भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2938
उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2026

अमृतसर और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएनएल का पुनरुद्धार

2938. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), जो कभी पंजाब, विशेषकर अमृतसर जैसे सीमावर्ती जिलों में दूरसंचार व्यवस्था की रीढ़ था, अब कमजोर अवसंरचना, अपर्याप्त अनुरक्षण, कर्मचारियों की कमी, फाइबर एवं डिश कनेक्टिविटी के अभाव तथा वर्तमान की 5जी सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण निरंतर कमजोर होता जा रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का पंजाब में बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए कोई व्यापक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है, जिसमें टावर अवसंरचना का उन्नयन, 5जी सेवाओं की शुरुआत, फाइबर कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण, स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा सीमावर्ती गांवों में, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संपर्क दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विश्वसनीय दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करना शामिल है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए किसी विशेष पैकेज पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) से (ग) आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप, बीएसएनएल ने दिनांक 25.07.2026 तक पूरे भारत में एक लाख साइटों में से 98,550 स्वदेशी 4जी साइटें संस्थापित की हैं, जिनमें से 97,174 4जी साइटें ऑन-एयर हैं। ये उपकरण प्रौद्योगिकी की दृष्टि से 5जी में अपग्रेड करने योग्य हैं। पंजाब में, बीएसएनएल ने अमृतसर जैसे सीमावर्ती जिलों में 944 4जी साइटों सहित कुल 4,094 4जी साइटें संस्थापित की हैं। भारतनेट परियोजना के तहत, दिनांक 30.06.2026 तक पंजाब में 10,189 ग्राम पंचायतें (जीपी) कार्यशील हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने सहित सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में मांग के आधार पर हाई-स्पीड फाइबर कनेक्टिविटी हेतु सरकार द्वारा दिनांक 04.08.2023 को 1.39 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को अनुमोदित किया है। बीएसएनएल इस कार्यक्रम के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है।

सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज का और आगे विस्तार करने के लिए, सरकार ने 4जी सैचुरेशन स्कीम, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)/बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट (बीआईपी) आदि जैसी विभिन्न स्कीमों को अनुमोदित किया है।

*****